



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082020-220887
CG-DL-E-06082020-220887

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2020/श्रावण 14, 1942

No. 187]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2020/SHRAVANA 14, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2020

(मध्यावधि समीक्षा)

मामला सं. एडी-एमटीआर-08/2020

विषय: चीन जन.गण., जापान और कोरिया गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'टोल्यूने डी-आइसोसाइनेट (टीडीआई)' के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के संबंध में कोरिया गण. से उत्पादक/ निर्यातक के नाम में परिवर्तन के लिए सीमित मध्यावधि समीक्षा की शुरूआत।

फा. सं.07/22/2020-डीजीटीआर.—हानवा सोल्युशन कॉर्पोरेशन (जिसे पहले हानवा कैमिकल कॉर्पोरेशन कहा जाता था), कोरिया गण. (जिसे यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चीन जन.गण., जापान और कोरिया गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'टोल्यूने डी-आइसोसाइनेट (टीडीआई)' (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए दिनांक 13 दिसंबर, 2017 की अधिसूचना सं. 14/36/2016-डीजीएडी द्वारा अंतिम जांच परिणाम में

नाम में परिवर्तन के लिए यह आवेदन दायर किया है। आवेदक विचाराधीन उत्पाद का एक विदेशी उत्पादक/निर्यातक है और कंपनी कोरिया कार्मशियल कोड के अंतर्गत कोरिया गणराज्य में अधिनियमित है।

क. पृष्ठभूमि

- 1995 और उसके बाद यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने कोरिया गण., चीन जन.गण., जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “टोल्याने डी- आइसोसाइनेट (टीडीआई)” के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए दिनांक 13, दिसंबर, 2017 की अधिसूचना सं. 14/36/2016-डी जी ए डी द्वारा अपने अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे।
- केन्द्र सरकार ने दिनांक 23 जनवरी, 2018 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 3/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया था।

ख. विचाराधीन उत्पाद

- वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) चीन जन.गण., जापान और कोरिया गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “टोल्याने डी- आइसोसाइनेट (टीडीआई)” है। आवेदन में विचाराधीन उत्पाद, जो पूर्ववर्ती जांचों के समान रहेगा, को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

“टोल्याने डी- आइसोसाइनेट (टीडीआई) एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र $\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_3$ (एनसीओ) 2 है। 6 संभव आइसोमर में से 2 वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण हैं: 2, 4-टीडीआई (सीएस: 584-84-9) तथा 2, 6-टीडीआई (सीएस: 91-08-7)। 2, 4-टीडीआई को शुद्ध रूप में उत्पादित किया जाता है परंतु टीडीआई को प्रायः 2, 4 और 2, 6 आइसोमर के क्रमशः 80/20 और 65/35 मिश्रण के रूप में बेचा जाता है। वर्तमान जांच में पीयूसी ऐसे टीडीआई से संबंधित है जिसकी आइसोमर मात्रा (80:20) के अनुपात में है और कोई अन्य ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है।

टीडीआई एक स्पष्ट तरल होता है और इसका प्रयोग फ्लैक्सीबल पॉलीयूरेथियम फोम, फर्नीचर कुशन, औद्योगिक गैस किट, खेल और चिकित्सा प्रयोग के लिए प्रोटेक्टिव पैड्स, ऑटोमोबाइल्स: शीट, फर्नीचर, लाइनिंग, सन वाइजर्स आदि, पैकिंग: इलेक्ट्रॉनिक मर्चे, फ्रोजन खाद्य, दवाइयों, ऑडियो वीडियो कंप्यूटर सीडी आदि के उत्पादन में होता है।

एक कार्बनिक रसायन होने के कारण टीडीआई को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 तथा आगे उपशीर्ष 29291020 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है जो ‘टोल्याने डी- आइसोसाइनेट से संबंधित है, तथापि, जैसा आयोजक ने बताया है, इस शीर्ष में आइसोमर (80:20) से इतर कतिपय ग्रेड शामिल हैं और इसलिए वर्गीकरण केवल सांकेतिक है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि संबद्ध वस्तुओं के आयात कुछ अन्य उप शीर्षों जैसे 29094300, 29291090, 29291010, 38249090 और 39095000 के अंतर्गत होने की भी जानकारी मिली है। डी जी सी आई एंड एस के अनुसार आयात आंकड़ों की जांच से पता चलता है कि पी ओ आई के दौरान आयात उप शीर्ष सं. 29291020 के अंतर्गत हुए थे और उपशीर्ष 29291010 तथा 29291090 के अंतर्गत भी पर्याप्त मात्रा में आयात हुए थे। अतः सीमाशुल्क वर्गीकरण को केवल सांकेतिक रूप में माना गया है और वह जांच में पीयूसी के दायरे और लागू किए जाने के लिए अनुशंसित किसी उपाय, यदि कोई हो, पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

5. इस मध्यावधि समीक्षा के लिए विचाराधीन उत्पाद अपरिवर्तित रहेगा।

ग. शामिल देश

6. वर्तमान समीक्षा जांच में शामिल देश कोरिया गण. (जिसे संबद्ध देश भी कहा गया है) है।

घ. समीक्षा के लिए आधार

7. हानवा सोल्यूशन कॉर्पोरेशन ने यह बताते हुए एक मध्यावधि समीक्षा आवेदन दायर किया है कि हानवा कैमिकल कॉर्पोरेशन के उसके पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हानवा क्यू सैल एंड एडवांस मेटेरियल कॉर्पोरेशन के साथ विलय के परिणामस्वरूप केवल नाम में परिवर्तन हुआ है और आवेदक के शेयरधारित ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह दावा किया गया है कि मूल कंपनी का नाम हानवा कैमिकल कॉर्पोरेशन के साथ हानवा क्यू सैल एंड एडवांस मेटेरियल कॉर्पोरेशन के विलय के पश्चात 6 जनवरी, 2020 को बदल गया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि इसके मद्देनजर उनके सभी निर्यात हानवा सोल्यूशन कॉर्पोरेशन के नाम से होंगे और तदनुसार, हानवा कैमिकल कॉर्पोरेशन पर लागू शुल्क हानवा सोल्यूशन कॉर्पोरेशन पर भी लागू किया जाना चाहिए क्योंकि इनकी कंपनी समान है।

ड. जांच शुरुआत

8. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम और उनके अंतर्गत निर्मित पाटनरोधी निमावली में पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की जरूरत की प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर समीक्षा किया जाना अपेक्षित है।

9. आवेदक द्वारा कोरिया गणराज्य से उत्पादक/निर्यातक के नाम में परिवर्तन तक सीमित मध्यावधि समीक्षा की आवश्यकता दर्शाने वाली परिवर्तित परिस्थितियों संबंधी प्रदत्त सूचना को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना सं. 14/36/2016-डीजीएडी दिनांक 13 दिसंबर, 2017 द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों और संबंधित पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9 क (5) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 23 जनवरी, 2018 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 3/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा लगाए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करना अब उचित समझते हैं। वर्तमान समीक्षा अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/36/2016-डीजीएडी दिनांक 13 दिसंबर, 2017 और सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 3/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 23 जनवरी, 2018 के संबंध में है। हानवा सोल्यूशन कॉर्पोरेशन द्वारा दावा किए गए नाम में परिवर्तन के पहलु तक सीमित है।

च. जांच की अवधि

10. चूंकि वर्तमान समीक्षा जांच केवल नाम में परिवर्तन तक सीमित है, इसलिए प्राधिकारी समझते हैं कि जांच अवधि संगत नहीं है।

छ. प्रक्रिया

11. नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ज. सूचना प्रस्तुत करना

12. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देन निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg13-dgtr@gov.in और adv12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए और उसकी प्रति dir16-dgtr@gov.in तथा dd13-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए।

13. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

14. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
15. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
16. हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.dgtr.gov.in> को नियमित रूप से देखने की सलाह भी दी जाती है।

झ. समय-सीमा

17. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पत्तों adg12-dgtr@gov.in तथा adv12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने की तारीख या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
18. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

ञ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

19. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसका पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
20. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को यदि उसके किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है तो उसके 2 सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित है :

क. गोपनीय रूप में अंकित एक सैट (शीर्षक, पृष्ठ सं., सूची आदि सहित), और

ख. अगोपनीय रूप में चिह्नित दूरा सैट (शीर्षक, पृष्ठ सं., सूची आदि सहित)

21. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
22. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
23. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशिकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना

चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

24. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
25. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
26. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ट. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

27. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। इलैक्ट्रॉनिक रूप में सार्वजनिक फाइल को रखे जाने के तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

ण. असहयोग

28. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

बिद्युत बिहारी स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2020

(Midterm Review)

Case No. AD-MTR-08/2020

Subject: Initiation of Mid-Term Review limited to change of name of producer/exporter from Korea RP regarding anti-dumping duty imposed on imports of "Toluene Di-Isocyanate (TDI)" originating in or exported from China PR, Japan and Korea RP.

F.No.7/22/2020-DGTR.—A Mid-Term Review application has been filed by Hanwha Solutions Corporation (formerly called Hanwha Chemical Corporation), Korea RP (hereinafter referred to as "Applicant") for change in name in the Final Findings issued by Designated Authority vide Notification No. 14/36/2016-DGAD dated 13th December 2017 recommending definitive anti-dumping duty on the imports of "Toluene Di-Isocyanate" (TDI) (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR, Japan and Korea RP. The Applicant is a foreign Producer/Exporter of the product under consideration and the company is incorporated in the Republic of Korea, under the Korea Commercial Code.

A. Background

2. In accordance with Customs Tariff Act, 1975, as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules), the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) had issued its final findings vide Notification No. 14/36/2016-DGAD dated 13th December 2017 recommending definitive anti-dumping duty on the imports of “Toluene Di-Isocyanate” (TDI) originating in or exported from Korea RP, China PR, Japan.
3. The Central Government, vide Customs Notification No. 3/2018-Customs (ADD) dated 23rd January 2018, had imposed definitive anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

B. Product under consideration

4. The product under consideration (PUC) in the present investigation is Toluene Diisocyanate (TDI) originating in or exported from China PR, Japan and Korea RP. The product under consideration in the application is the same as the previous investigations, which was defined as follows-

“Toluene di-isocyanate (TDI) is an organic compound with the formula CH₃C₆H₃(NCO)₂. Two of the six possible isomers are commercially important: 2, 4-TDI (CAS: 584-84-9) and 2, 6-TDI (CAS: 91-08-7). 2, 4-TDI is produced in the pure state, but TDI is often marketed as 80/20 and 65/35 mixtures of the 2, 4 and 2, 6 isomers respectively. The PUC in the present investigation concerns TDI having isomer content in the ratio of (80:20) and any other grades are beyond the scope of product under consideration.

TDI is a clear liquid and is used for production of Flexible Polyurethane Foam, Furniture cushion, Industrial Gaskets, Protective pads for Sports & Medical use, Automobiles: Seats, Furniture, Lining, Sun visors etc., packing: Electronic items, Frozen Foods, Medicines, Audio-video Computer CD's etc.

TDI being an organic chemical is categorized under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under subheading 29291020 which pertains to Toluene diisocyanate. However, as submitted by the applicant, this heading includes certain grades other than isomers (80:20) hence the classification is indicative only. It has also been claimed by the applicant that the imports of the subject goods have been reported under some other subheadings also such as 29094300, 29291090, 29291010, 38249090 and 39095000. An examination of the import data as per DGCI&S shows that imports during POI were under subheading number 29291020 and there were substantial imports under subheading 29291010 and 29291090 also. Hence, the Customs classification is treated as indicative only and in no way binding on the scope of the PUC in the investigation and any measures to be recommended to be imposed, if any.”

5. The product under consideration for this mid-term review remains unchanged.

C. Country Involved

6. The country involved in the present review investigation is Korea RP (also referred to as “subject country”).

D. Grounds for Review

7. Hanwha Solutions Corporation has filed a Mid-Term Review application stating that a merger of Hanwha Chemical Corporation with its wholly owned subsidiary Hanwha Q Cells and Advanced Materials Corporation has resulted in a name change only, and there has been no change in the shareholding structure of the applicant. It has been claimed that the original company name has changed on 06th January 2020 following merger of Hanwha Q Cells and Advanced Materials Corporation with Hanwha Chemical Corporation. They have further claimed that in view of the same, all their exports will be in the name of Hanwha Solutions Corporation, and accordingly, the duty applicable on Hanwha Chemical Corporation must be made applicable to Hanwha Solutions Corporation as the entity is the same.

E. Initiation

8. The Customs Tariff Act, and the Anti-dumping Rules made thereunder, requires the Authority to review from time to time the need for continuance of anti-dumping duties.
9. Having regard to the information provided by the applicant indicating changed circumstances necessitating a mid-term review limited to change of name of producer/exporter from Korea RP, the Designated Authority now considers it appropriate to conduct a Mid Term Review of the Final Findings notified vide Notification No. 14/36/2016-DGAD dated 13th December 2017 and the

definitive anti-dumping duty imposed vide Customs Notification No. 3/2018-Customs (ADD) dated 23rd January 2018, in terms of the provisions of Section 9A (5) of Customs Tariff (Amendment) Act 1995 read with Rule 23 of the anti-dumping Rules supra. The present review is limited to the aspect of name change claimed by M/s Hanwha Solutions Corporation with regard to the Final Findings Notification No. 14/36/2016-DGAD dated 13th December 2017 and Customs Notification 3/2018-Customs (ADD) dated 23rd January 2018.

F. Period of Investigation

10. Since the present review investigation is restricted to only change of name, the Authority considers that the period of investigation is not relevant.

G. Procedure

11. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

H. Submissions of Information

12. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in and adv12-dgtr@gov.in, with a copy to dir16-dgtr@gov.in, and dd13-dgtr@gov.in.
13. The known producers/exporters in the subject country, their government through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.
15. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to other interested parties.
16. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

I. Time Limit

17. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg12-dgtr@gov.in and adv12-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
18. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

J. Submission of information on confidential basis

19. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
20. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:
 - a. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
 - b. the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).
21. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions
22. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other

information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
26. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

K. Inspection of Public File

27. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

L. Non-cooperation

28. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BIDYUT BEHARI SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority